पिट्स

आर.एन.आई. ३८१३९/८१

www.pits.co.in

वर्ष २९ अंक-४२ सोमवार, ८ जून २००९ पृष्ठ १६ मूल्य दो रुपये इंदौर, मुंबई से एक साथ प्रकाशित

बेचारे राज्यमंत्री

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर की गई टिप्पणी पूरी गोपनीयता बरतने की हिदायत के बावजूद अखबारों में छप गई। यह खबर लीक किसने की, इसे लेकर तगड़ा अनुसंधान चला। कुछ के निशाने पर आए पिछली सरकार में सड़क से जुड़े रहे मंत्री। कहा गया कि पुराना विभाग पाने की बेताबी में बात लीक की गई, लेकिन कैबिनेट की औपचारिक बैठक के बाद इस मसले पर पहली बार राज्यमंत्री बने एक ऐसे नेता सीएम की फटकार खा गए, जिनके क्षेत्र में पूरा जोर लगाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजय झेलनी पड़ी थी। राज्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा किसी खबरची से सीधा संबंध नहीं होने के बावजूद तोप का मुंह उनकी ओर कैसे हो गया।

तत्र रमते देवता

जून के शुरूआती दिन कुछ शुभ संदेश ला रहे हैं। देश में स्त्री शक्ति के सम्मान के दिन अब करीब दिख रहे हैं। देवी की तरह पूजी जाने वाली महिलाएं एक सदी तक प्रताड़ना झेलती रही। इस सदी में बदलाव की उम्मीद है। हालांकि हर शताब्दी में एक क्रांतिकारी नाम रहा है जिसने परंपराओं को बदलने का प्रयास किया। ऐसा भी नहीं कि प्रताड़नाओं का ग्राफ एकदम कम हो जाएगा। ऊंचाई चढ़ती स्त्री को नीचे खींचने के लिए पुरूष किसी भी स्तर तक जाता है। ऐसा ही कुछ प्रयास जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव कर रहे हैं। महिला आरक्षण के बिल को लेकर उनका रोष खुलकर सामने आ गया है। काली पट्टी या भूख हड़ताल के बजाय विरोध के एक अन्य तरीके को अपनाते हुए उन्होंने आत्महत्या की बात कही। कहीं न कहीं ये उनके भीतर का डर है कि स्त्री के सर्वोच्च होते ही उनकी प्रजाति को अगले-पिछली गलतियों की सजा न भुगतनी पड़ जाए। स्वभाव से निर्मल औरत नया अध्याय लिखने से पहले पुराने को पूरी तरह से बंद कर देती है। हर स्त्री का ये मानना है कि पुराने दुखों को ढोने से

उत्तम झंवर

नए खुशियों में बाधा स्वत: ही आ जाती है। सौ दिन में एक नया अध्याय शुरू हुआ तो लगभग 250 ऐसी महिला प्रतिनिधी होंगी जो संसद में अपनी बात रख सकेंगी। शरद और उनकी पार्टी ही नहीं इससे हर वो व्यक्ति चिंतित है जो स्त्री को आज भी केवल भोगना चाहता है। बात अपनी पसंद का खाना खाने की हो या जीवनसाथी चुनने की या फिर भावों को व्यक्त करने की। आजादी तो कहने भर की है। मेरा मानना है औरत ने भी अब चाहे प्रेम से चाहे लड़ कर अपने अधिकारों को पाने की जिद कर ही ली है। इन प्रतिनिधियों के आने से गांवों-कस्बों की उन औरतों का मनोबल बढ़ने के साथ नया आसमां भी मिल सकेगा जो आज भी घर की चारदिवारी के भीतर ही अपनी दुनियां को समेटे हैं। मजबूरी तो कहीं न कहीं होगी ही लेकिन हिम्मत का ग्राफ नही बढ़ पाया। बड़े शहरों की वे महिलाएं जो अपने माद्दे को साबित कर रही हैं उनके समकक्ष आने के लिए इन महिलाओं को एक ऐसी सीढ़ी चाहिए जो कम से कम इतना शिक्षित बना सके कि वे अपनी बात प्रमुखता से रख सकें। देवताओं को फिर से देश की उन्नति के लिए मनाने के लिए नारी को पूजनीय बनाना होगा। स्वार्थ की खातिर ही सही सम्मान का एक कदम सदजता ले आएगा।

मल्टीप्लैक्स मालिकों और निर्माताओं में हुी सुलह ने एक बड़े सेक्टर को बचा लिया। अन्यथा कुछ ही समय में फिल्म लाइन से जुड़े लोगों की बर्बाद दास्तानें सामने आ जातीं। समस्या तो अब भी है क्योंकि वर्ल्ड कप दर्शकों को मल्टीप्लैक्स तक आने नहीं देगा। खुशियों के साथ संघर्ष के पथ भी हर बार की तरह हर क्षेत्र में तैयार हैं। कामना करें हर औरत की हर इंसान की जीत की...।

महिलाओं को संसद व राज्य विधान मंडलों में 33 फीसदी आरक्षण दिलाने के अपनी 100 दिन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करने के यूपीए सरकार के इरादों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक भूचाल की तैयारी हो गई है. 15 वीं लोकसभा गठन के साथ ही महिलाओं की राजनीति और सत्ता में भागीदारी की गूंज तेज हो गई है. राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहली बार प्रतिभा पाटिल के रूप में एक महिला के आसीन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के सिंहासन पर एक दलित महिला मीरा कुमार का चुना जाना भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है. महिला आरक्षण बिल पर एक बार फिर अंतहीन बहस शुरू हो गई है.

महिला शक्ति की बढ़ती ताकत

महिला सशक्ति करण राग के साथ सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा जहां इस बिल के पक्ष में एक साथ खड़े हैं वहीं दोनों पक्षों के दलित और पिछड़े नेताओं के दल महिला आरक्षण को लेकर विरोध में लामबंद होते दिखाई दे रहे है. हालांकि आज देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं काबिज है और देश की संसद में भी आजादी के बाद से सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची है. फिर भी आबादी के मान से यह संख्या बहुत कम है. फिर भी एक बात तय है कि महिला आरक्षण को लेकर देश में सार्थक बहस की शुरूआत हो गई है. हालांकि पिछले दस से ज्यादा वर्षों से महिला आरक्षण बिल पास होने की बांट जोह रहा है लेकिन हर बार लोकसभा

के आखरी सत्र में इस बिल पर विचार शुरू होकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. पहली बार इसे गंभीरता के साथ शुरूआत में ही उठाया गया है. देश में महिलाएं राज कर सकती है और अच्छा शासन प्रशासन चला सकती है यह बात एक नहीं कई बार सिद्ध हो चुकी है. इसी के चलते आज देश में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, रेलमंत्री ममता बनर्जी, सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री मायावती और केन्द्र में सत्तारुढ़ गठबंधन की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी के अलावा लोकसभा में 59 सांसद राज्यसभा में कई सांसद राज्यों में विधायक और सफल मंत्री इस बात का सबूत है कि महिलाएं देश को सफल नेतृत्व दे सकती हैं.

शेष अंतिम पेज पर .....

संगमा नतमस्तक, पवार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से बगावत करने वाले दो दिग्गजों में से एक पीए संगमा को नतमस्तक कराने के बाद कांग्रेस आलाकमान की नजर अब शरद पवार पर है। कांग्रेस के रणनीतिकार पवार के लिए दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। पहले तो उन्हें मनचाहे मंत्रालय देकर एहसान से लाद दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र इकाई विलासराव देशमुख की अगुवाई में अगले विधानसभा चुनाव में 'एकला चलो' का राग छेड़कर पवार पर दबाव बना रही है। लगातार इस तरह के संदेश उछाले जा रहे हैं कि अगर मराठा सरदार पवार नहीं माने तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश का एकला चलो का प्रयोग महाराष्ट्र में भी अपना सकती है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी महासचिव राहुल गांधी जहां संगठन के पेंच कसना चाह रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश तो सर्वोच्च वरीयता पर है ही, बाकी वे राज्य हैं जहां जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख के नजदीकी भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी महाराष्ट्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं।

शेष अंतिम पेज पर .....